2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच 'टू प्लस टू' वार्ता का फैसला किया गया था। अभी तक इसकी एकमात्र बैठक हुई जो कि दिल्ली में अक्टूबर, 2018 में हुई थी।

ग्लोबल इकोनॉमी काफी हद तक भारत जैसे देशों पर निर्भर : मोदी

बोले ▸ आर्थिक अनिश्चितता की वजह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का असंतुलन

'अरब न्यूज' को दिए साक्षात्कार में बोले प्रधानमंत्री

रियाद, प्रेट्र : बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के 'असंतुलन' को आर्थिक अनिश्चितता की वजह बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (ग्लोबल इकोनॉमी) काफी हद तक भारत और सऊदी अरब जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार किए गए 'मार्ग' पर निर्भर है। हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने कहा था कि अमेरिका-चीन व्यापार विवाद और अन्य वैश्विक विवादों की वजह से इस साल वैश्विक वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहेगी। 2018 में वैश्विक वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी।

सोमवार रात सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एक साक्षात्कार मंगलवार को 'अरब न्यूज' में प्रकाशित हुआ। इसमें मोदी ने कहा, 'वैश्विक आर्थिक परिदृश्य काफी हद तक भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा तैयार मार्ग पर निर्भर है। मैंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में कहा था कि हमारा ईमानदारी से मानना है कि सभी की वृद्धि के लिए हमें समन्वित प्रयासों की जरूरत है। इसमें सभी का भरोसा भी होना चाहिए।' 'जी-20 में भारत और सऊदी अरब असमानता दूर करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' यह पूछे जाने पर कि भारत और सऊदी अरब सहित अन्य देशों को वैश्विक आर्थिक सुस्ती से कैसे निपटना चाहिए, मोदी ने कहा, भारत ने कारोबार के अनुकूल माहौल पैदा करने के लिए कई सुधार किए है। इसका नतीजा है कि विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 2019 में भारत 63वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2014 में इस सूची में भारत 142वें स्थान पर था। सुधारों का मकसद यह भी है कि हम वैश्विक वृद्धि और स्थिरता के लिए प्रमुख भूमिका में रहें। उन्हें खुशी है कि सऊदी अरब ने भी अपने दृष्टिकोण 2030 के तहत सुधार कार्यक्रम शुरू किया है।

भारत-सऊदी अरब में बढ़ रहा सुरक्षा सहयोग : पीएम ने कहा, आतंकवाद से मुकाबला करने सहित सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर भारत और सऊदी अरब के बीच आपसी सहयोग बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। 'मेरा मानना है कि भारत और सऊदी अरब जैसी एशियाई शक्तियां अपने-अपने पड़ोस में समान रूप से सुरक्षा चिंताओं को साझा करती हैं। मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में रियाद का दौरा किया था जो बेहद सार्थक रहा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी, रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त समिति है जो नियमित बैठकें करती है। हमने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी हित और सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की है। दोनों देश सुरक्षा सहयोग और रक्षा उद्योगों में सहयोग पर समझौते करने की प्रक्रिया में हैं और एक व्यापक सुरक्षा संवाद तंत्र बनाने पर भी दोनों देश सहमत हैं।'

क्रेता-विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ रहे दोनों देश : प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब क्रेता-विक्रेता संबंधों से करीबी रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें सऊदी अरब का भारत के तेल एवं गैस परियोजनाओं में निवेश शामिल है। मोदी ने कहा, 'सऊदी अरैमको भारत के पश्चिमी तट पर बड़ी रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल परियोजनाओं में हिस्सेदारी कर रही है। हमें अरैमको की भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में हिस्सेदारी की भी उम्मीद है।' सऊदी अरैमको दुनिया की सर्वाधिक लाभकारी कंपनी है। इसका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार पर नियंत्रण है। वहीं, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के मामले में इराक के बाद सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। भारत अपने कच्चे तेल के आयात की 18 फीसद जरूरत सऊदी अरब से पूरी करता है।

भारतीय समुदाय का परिश्रम संबंधों को मजबूत बनाने में मददगार : प्रधानमंत्री ने कहा कि सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और प्रतिबद्धता ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में काफी मदद की है। उन्होंने कहा, 'करीब 26 लाख भारतीयों ने सऊदी अरब को अपना दूसरा घर बना लिया है। वे उसकी वृद्धि और विकास में योगदान दे रहे हैं। कई भारतीय हर साल हज, उमराह और कारोबारी वजहों से सऊदी अरब की यात्रा करते हैं।' भारतीय समुदाय को अपना संदेश देते हुए मोदी ने कहा, 'सऊदी अरब में आपने अपने लिए जो स्थान बनाया है, भारत को उस पर गर्व है।

भारत के खुदरा तेल कारोबार में निवेश करेगा सऊदी अरब

नई दिल्ली, रायटर : पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सऊदी अरब की कंपनियां भारत के ऑयल और गैस रिटेलिंग सेक्टर में निवेश की तैयारी कर रही हैं। इसमें दोनों देशों के हित शामिल होंगे। समझौते के बाद सऊदी अरब को भारत में एक स्थायी खुदरा बाजार मिल सकेगा। ज्ञात हो, सऊदी अरब की कंपनी अरैमको और यूएई की कंपनी एडनॉक ने भारत की सरकारी कंपनियों के साथ प्राथमिक समझौता किया है। इसके तहत ये कंपनियां भारत के पश्चिमी तट पर 12 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली रिफाइनरी लगाएंगी। इस रिफाइनरी में इन कंपनियों की 50 परसेंट हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा सरकार भारत पेट्रोलियम में अपनी 53 .29 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है।

'दावोस इन द डेजर्ट' में सऊदी किंग से की मुलाकात

रियाद, प्रेट्र : 'दावोस इन द डेजर्ट' सम्मेलन में भाग लेने दो दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और घटनाओं की निंदा करते हुए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। सऊदी किंग ने प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन भी किया। 'दावोस इन द डेजर्ट' सम्मेलन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक सम्मेलन की तर्ज पर हो रहा है। इसमें इससे जुड़े देशों में निवेश की भावी संभावनाओं पर विचार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी और किंग सलमान के बीच बैठक और भोज के बाद प्रधानमंत्री के आर्थिक संबंधों के सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद की सभी रूपों और घटनाओं की निंदा करते हुए द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच कृषि, तेल एवं गैस, समुद्री सुरक्षा, नवीन प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों में सहयोग, सुरक्षा सहयोग, हवाई सेवा समझौते, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा उत्पादों के नियमन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। त्रिमूर्ति ने बताया कि राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को राजधानी रियाद में सऊदी अरब किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज एल साउद से मुलाकात हुई। एएनआइ

कई सऊदी मंत्रियों ने की मोदी से मुलाकात : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान, श्रम व सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अलराजी और पर्यावरण, जल व कृषि मंत्री अब्दुल रहमान बिन अब्दुलमोहसेन अल फेडली ने मुलाकात की। सऊदी अरब के मंत्रियों से चर्चा सार्थक रही। खासतौर से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई।

रायगढ़ की महत्वाकांक्षी परियोजना पर अहम चर्चा : सऊदी ऊर्जा मंत्री अजीज के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खासतौर पर अहम है क्योंकि दोनों देशों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पश्चिमी तट पर बड़ी रिफाइनरी परियोजना लगाने का फैसला किया है। इसमें सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी अरैमको और भारत की सरकारी तेल कंपनियां बड़ा निवेश करने वाली हैं।

पीएम मोदी की दूसरी सऊदी अरब यात्रा : प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह 2016 में यहां आए थे। इसी साल फरवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिल सलमान भारत आए थे। बीते कुछ साल में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 27.48 अरब डॉलर का रहा। इस तरह सऊदी अरब भारत का चौथा बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। सऊदी अरब ने पिछले माह घोषणा की कि वह भारत के ऊर्जा, पेट्रो कैमिकल, रिफाइनिंग, बुनियादी ढांचे, कृषि व खनन क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

जॉर्डन के किंग से भी मिले मोदी : रियाद में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, खासकर व्यापार और निवेश में परस्पर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। जॉर्डन में 10 हजार भारतीय रहते हैं।

▸ दोनों नेताओं ने की आतंकवाद की निंदा, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल खपतकर्ता देश

- अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल खपतकर्ता देश है।
- भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 83 फीसद आयात करता है।
- वर्ष 2018-19 में सऊदी अरब ने 4 .33 करोड़ टन कच्चा तेल भारत को बेचा, जबकि भारत ने कुल 20 .73 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत सऊदी अरब से हर माह दो लाख टन एलपीजी खरीदता है।

जस्टिस बोबडे होंगे अगले मुख्य न्यायाधीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जस्टिस शरद अरविंद बोबडे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मंगलवार को राष्ट्रपति ने जस्टिस एसए बोबडे को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 17 नवंबर को रंजन गोगोई के सेवानिवृत्त होने के बाद 18 नवंबर को जस्टिस बोबडे पद की शपथ लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बोबडे ने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जिसमें अयोध्या राम जन्मभूमि मामला भी शामिल है। मंगलवार को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस एसए बोबडे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 18 नवंबर से प्रभावी होगी।

जस्टिस बोबडे का जन्म 24 अप्रैल 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने के बाद 1978 में वह महाराष्ट्र बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पर पंजीकृत हुए और उन्होंने बांबे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष वकालत शुरू की। उन्होंने नागपुर पीठ के अलावा बांबे हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और सुप्रीम कोर्ट में भी 21 वर्ष से ज्यादा समय तक वकालत की। 1998 में वह वरिष्ठ वकील नामित हुए। संवैधानिक, प्रशासनिक, कंपनी, पर्यावरण और चुनाव कानून में उनकी विशेषज्ञता है।

जस्टिस बोबडे 29 मार्च 2000 को बांबे हाई कोर्ट मे एडिशनल न्यायाधीश नियुक्त हुए और 28 मार्च 2002 को स्थाई न्यायाधीश नियुक्त हुए। 16 अक्टूबर 2012 को वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 12 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत होंगे। उनका मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल एक वर्ष पांच महीने का होगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस बोबडे ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए जिसमें निजता का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित करने का फैसला, आधार न होने के कारण किसी भी नागरिक सरकारी सेवाओं के लाभ और मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता तथा प्रदूषण के चलते 2016 में दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला शामिल है।

▸ राष्ट्रपति ने जस्टिस एसए बोबडे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
▸ रंजन गोगोई के सेवानिवृत होने के बाद जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को पद की शपथ लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने मंगलवार को नई दिल्ली में जस्टिस एसए बोबडे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। एएनआइ

एजेंट से बुक कराए गए रेल टिकट के लिए ओटीपी रिफंड प्रणाली

नई दिल्ली, प्रेट्र: अधिकृत रेलवे एजेंटों के जरिये टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत आइआरसीटीसी ओटीपी आधारित प्रणाली लेकर आया है, जो यात्रियों को टिकट कैंसल कराने और आइआरसीटीसी द्वारा दिए गए पासवर्ड का इस्तेमाल कर रिफंड पाने की सुविधा देगा।

आइआरसीटीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह प्रणाली केवल उसके अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराए गए ई-टिकटों पर लागू होगी। नई प्रणाली के तहत, जब भी कोई यात्री अधिकृत आइआरसीटीसी एजेंट के जरिये बुक कराए गए टिकट या पूर्ण वेटलिस्ट टिकट कैंसल कराता है तो रिफंड राशि और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का एक एसएमएस यात्री के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यात्री को रिफंड पाने के लिए एजेंट के साथ यह ओटीपी साझा करना होगा। आइआरसीटीसी के एक अधिकारी ने प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया कि अब जब रिफंड ओटीपी आधारित होगा।

रक्षा तकनीकी सहयोग होगा अमेरिका के साथ अगली 'टू प्लस टू' वार्ता के केंद्र में

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्ष 2015 में भारत-अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में संयुक्त तौर पर अत्याधुनिक तकनीक वाले रक्षा उपकरणों को विकसित करने का एक समझौता हुआ था। विगत चार वर्षों में इस समझौते के तहत कोई जमीनी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है, लेकिन अब इस समझौते की सूरत बदलने वाली है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच गठित फोरम डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (डीटीआइआइ) की पिछले हफ्ते नई दिल्ली में हुई बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इसमें एक फैसला यह है कि अब संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले रक्षा उपकरणों को लेकर समयबद्ध और साफ लक्ष्यों के साथ काम किया जाएगा और दोनों देशों की तरफ से गठित विशेष समिति इसकी लगातार निगरानी करेगी। इस बारे में दिसंबर, 2019 में अमेरिका में दोनों देशों की 'टू प्लस टू' वार्ता के दौरान हस्ताक्षर किए जाने के संकेत दिए गए हैं।

'टू प्लस टू' वार्ता का फैसला जून, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई पहली आधिकारिक बैठक में किया गया था। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री सदस्य होते हैं। अभी तक इसकी एकमात्र बैठक नई दिल्ली में अक्टूबर, 2018 में हुई थी। अमेरिकी सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि आगामी 'टू प्लस टू' बैठक में संयुक्त तौर पर विकसित होने वाले या निर्माण किए जाने वाले रक्षा उपकरणों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) पर भी अंतिम फैसला हो जाएगा। डीटीआइआइ की पिछले हफ्ते संपन्न बैठक में एसओपी के विभिन्न पहलुओं पर सहमति बन गई है। इसे अमेरिकी पक्षकारों ने एक बड़ी उपलब्धि के दौर पर चिह्नित किया है क्योंकि अब दोनों पक्षों को मालूम होगा कि एक दूसरे की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। साथ ही दोनों पक्षों को साथ-साथ काम करने की चुनौतियों और अवसरों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, डीटीआइआइ की बैठक में मुख्य तौर पर दोनों देशों की निजी रक्षा कंपनियों के बीच बेहद अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने को लेकर बात हुई है। दोनों तरफ के उद्योग किन-किन क्षेत्रों में काम करेंगे इसको परिभाषित करने वाले एक विशेष मसौदे पर आगामी 'टू प्लस टू' वार्ता में हस्ताक्षर होंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच फिलहाल दो सबसे अहम परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसमें एक है संयुक्त तौर पर अत्याधुनिक युद्धक विमान के लिए इंजन तैयार करना और दूसरा भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक विमानवाहक पोत का निर्माण। इन दोनों पर सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुआई में हुई द्विपक्षीय बैठक में बनी थी। इसे बाद में मोदी और ट्रंप ने भी आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि आगामी 'टू प्लस टू' वार्ता के बाद उक्त दोनों परियोजनाएं रफ्तार पकड़ सकती हैं।

कम या गलत सजा से जुड़े ज्यादा मामले होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि निचली अदालतों द्वारा कम या गलत सजा दिए जाने के चलते उसके सामने अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि निचली अदालतों से सजा निर्धारित करते समय सभी पहलुओं पर ध्यान देने को लेकर बार-बार कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा तय करने की प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी की। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। हाई कोर्ट ने चार लोगों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन-तीन साल की सजा को कम करते हुए उनके द्वारा जेल में बिताए गए दिनों के बराबर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा, 'उसके पास ज्यादातर मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें निचली अदालतों द्वारा कम या गलत सजा सुनाई गई होती है।

राष्ट्रपति कोविंद का सुझाव, अनाथों और दिव्यांगों पर अधिक खर्च करें कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कंपनियों को सुझाव दिया है कि वे कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अनाथ और दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए अधिक राशि खर्च करें। राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि सीएसआर गतिविधियों के जरिये विकास की चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान ढूंढे जा सकते हैं।

कोविंद ने पहले राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा, धन का दान करने पर सम्मान मिलता है, उसे जमा करने पर नहीं। कंपनी कानून, 2013 के तहत सीएसआर प्रावधान एक अप्रैल, 2014 से लागू हुए हैं। इसके तहत निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का दो फीसद एक वित्त वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि 2014-15 से कंपिनयां हर साल सीएसआर पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती हैं। उन्होंने कहा, समाज कल्याण गतिविधियों पर खर्च करने के लिए संसाधन, इच्छाशक्ति और रूपरेखा अहम होते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हमें किसकी अधिक मदद करनी चाहिए....? साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अनाथों और दिव्यांगों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि 2030 तक प्रत्येक अनाथ की देखरेख की जा सकेगी। अब से राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार हर साल दो अक्टूबर को दिए जाएंगे।

समारोह के बाद महिला पुलिसकर्मी को देखने पहुंचे राष्ट्रपति: समारोह समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति उस महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंचे जो गिर गई थी। दिल्ली की महिला पुलिसकर्मी विज्ञान भवन में मंच के सामने खड़ी थी। जिस समय राष्ट्र गान बजाया जा रहा था उसी दौरान वह गिर गई और बैठ गई। राष्ट्र गान समाप्त होने के बाद कोविंद को निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर के साथ बातचीत करते देखा गया। इसके बाद राष्ट्रपति सुरक्षाकर्मियों के साथ मंच से उतरकर महिला पुलिसकर्मी तक पहुंचे। आम तौर पर राष्ट्र गान समाप्त होने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल से विदा हो जाते हैं।

▸ राष्ट्रपति ने पहले राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार समारोह को संबोधित किया

राष्ट्रपति ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पहले राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व अवार्ड प्रदान किए। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित रहीं। प्रेट्र

'साझा स्टाफ' वाले तकनीकी संस्थानों पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंजीनियरिंग कालेज और अन्य तकनीकी संस्थानों के शिक्षक अब एक साथ दो कालेजों में नहीं पढ़ा सकेंगे। 'साझा स्टाफ' वाले तकनीकी संस्थानों पर कार्रवाई होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा में नियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) ने ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है।

एआइसीटीई ने इन तकनीकी संस्थानों को चेताते हुए कहा कि अगर उनके शिक्षकों को उसी संस्थान के किसी अन्य कालेज या किसी अन्य संस्थान में भी पढ़ाते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थानों को मिली मान्यता को भी रद किया जा सकता है। एआइसीटीई ने सभी मान्यताप्राप्त संस्थानों को भेजे पत्र में कहा है कि ऐसे गलत आचरण से ना सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि यह संस्थानों को मिली मंजूरी की शर्तों का भी उल्लंघन है।

पत्र में कहा गया है कि परिषद को यह जानकारी मिली है कि कुछ संस्थान अपने यहां पढ़ाए जा रहे कुछ पाठ्यक्रमों या तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में परिषद से मिली विस्तार की मंजूरी का उल्लंघन करते हुए विभागीय सदस्यों से एक ही संस्थान के दो कालेजों का काम करा रहे हैं या फिर शिक्षक एक नौकरी के साथ ही दूसरे कालेज में भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। एक साथ दो संस्थानों या दो स्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है। इससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। ऐसे आचरण में लिप्त कालेजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नगा वार्ता में दूसरे दिन भी गतिरोध बरकरार

नई दिल्ली, प्रेट्र : नगालैंड में सात दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या का अंतिम समाधान निकालने के लिए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन वार्ता में गतिरोध बरकरार रहा। केंद्र के वार्ताकार और राज्यपाल आरएन रवि ने एनएससीएन-आइएम और सात संगठनों के शीर्ष गठबंधन के साथ अलग-अलग वार्ता की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ वार्ता निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रही है, जबकि पूर्वोत्तर में बड़ा उग्रवादी समूह एनएससीएन-आइएम नगाओं के लिए अलग झंडे और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। घटनाक्रम से परिचित एक अधिकारी ने कहा, 'वार्ताकार ने सुबह एनएनपीजी और दोपहर में एनएससीएन-आइएम के साथ चर्चा की। जल्द ही फिर वार्ता होने की संभावना है।' मतभेद दूर करने, खासकर एनएससीएल-आइएम की मांग के संबंध में अड़चन दूर करने के लिए दिल्ली में वार्ता का आयोजन किया गया था। हालांकि, केंद्र अलग झंडे और अलग संविधान जैसी मांगों को पहले ही खारिज कर चुका है।

बड़े मामले

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, विभिन्न छुट्टियों के कारण गोगोई के पास कामकाज के लिए सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं

आठ कार्यदिवस में सीजेआइ को देने हैं कई फैसले

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले महज अगले आठ कार्यदिवस में वह रामजन्मभूमि, राफेल पर फैसले की समीक्षा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गलतबयानी समेत कई अहम मामलों पर अपना फैसला सुनाएंगे।

मौजूदा समय में सर्वोच्च अदालत में दीपावली का अवकाश है और सुप्रीम कोर्ट दोबारा आगामी चार नवंबर को खुलेगा। इसके बाद भी सर्वोच्च अदालत में आगामी 11 और 12 नवंबर को भी अवकाश रहेगा। इस लिहाज से मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर को रिटायर होने से पहले अदालत के पास कामकाज के लिए केवल आठ दिन ही बचे हैं।

सीजेआइ रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच जजों की एक और संविधानपीठ को राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील रामजन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाना है। इस फैसले तक पहुंचने के लिए 70 साल पुराने अदालती मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई की थी। अयोध्या में रामजन्मभूमि विवाद में सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला विगत 16 अक्टूबर को सुरक्षित कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्ष 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। इसमें से चार दीवानी मामले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीन पक्षों राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटा जाए।

▸ अयोध्या जन्मभूमि मामले पर 17 नवंबर से पहले आना है निर्णय
▸ सबरीमाला समेत कई मामलों पर चीफ जस्टिस गोगोई को देना है आदेश

रंजन गोगोई फाइल फोटो

राहुल गांधी और राफेल विमान सौदे पर आना है फैसला

गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ केरल में सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर फैसला सुनाएगी। इसके अलावा, गोगोई के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'चौकीदार चोर है' की गलतबयानी पर अपना फैसला सुनाएगी। वहीं, राफेल सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा करेगा। तब सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में फ्रेंच कंपनी दासौ से खरीदे 36 लड़ाकू विमानों के सरकारी सौदे को क्लीनचिट दे दी थी।

सूचना के अधिकार के मामले पर भी आएगा फैसला

विगत चार अप्रैल को पांच जजों की संविधान पीठ ने चीफ जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता में दिल्ली हाईकोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सूचना के अधिकार के दायरे में सीजेआइ का दफ्तर भी आता है।

छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू के रडार पर एक और आइएएस

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) एक और आइएएस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। 2004 बैच के इस आइएएस पर स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में एमडी रहने के दौरान भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगा है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है।

ईओडब्ल्यू के अफसरों के अनुसार मामला करीब 10 वर्ष पुराना 2009-10 का है। राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस बने उक्त अफसर उस वक्त कॉर्पोरेशन में एमडी थे। इस दौरान कार्पोरेशन में प्रबंध लेखा व उप प्रबंधक तकनीकी के तीन पदों पर भर्ती निकाली गई, लेकिन इसके लिए सरकार से अनुमति नहीं ली गई। इस मामले में कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी टी राधाकृष्णन ने 2016 से ही इन तीनों अधिकारियों को पद से हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईओडब्ल्यू ने शिकायत के बाद इसकी नए सिरे से जांच करने की तैयारी में है।

कह के रहेंगे माधव जोशी